भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2106
(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के अंतर्गत राज्यों के कार्यनिष्पादन का आंकलन

2106. डा. टी. एन. सीमा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत लाभ गरीब/गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की बजाय सरपंच सहित प्रभावशाली व्यक्तियों को मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने 'मनरेगा' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के कार्य-निष्पादन का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और इसमें पिछड़ने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार 'मनरेगा' को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुरस्कृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) और (ख) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानों के अनुसार, अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मांग करने पर कार्य दिया जाएगा। अधिनियम में मांग के अनुसार कार्य देने के उद्देश्य से किसी भी परिवार के लिए न तो प्राथमिकता है और न ही भेदभाव है।

(ग) और (घ) विभिन्न ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों/जिलों तथा राज्यों के निष्पादन को प्रतिदिन विभिन्न मापकों जैसे कि- सृजित श्रम दिवस, औसत आधार पर प्रति परिवार प्रदान किए गए औसत श्रम दिवस, 100 दिन पूरा करने वाले परिवारों का प्रतिशत, तालमेल के आधार पर किए गए कार्यों का प्रतिशत, पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत, उन अनु. जाति/अनु. जनजाति के जॉब-कार्ड धारकों का प्रतिशत जिन्हें कार्य दिया गया तथा समय पर किए गए भुगतान के प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह रिपोर्ट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है (रिपोर्ट संख्या -15.1) ।

(ङ.) मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 5 राज्यों अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, सिक्किम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को पुरस्कृत किया है।

*****